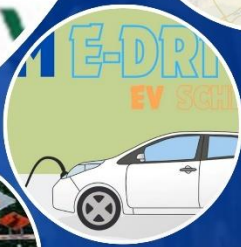


RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
सितम्बर
12
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

By Ankit Avasthi Sir

TAPI पाइपलाइन (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) परियोजना

हाल ही में अफगानिस्तान ने घोषणा की कि तुर्कमेनिस्तान में अधिकारियों के साथ मिलकर \$10 बिलियन की गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। यह TAPI पाइपलाइन (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) परियोजना है, जो दक्षिण एशिया में ऊर्जा आपूर्ति को मजबूती देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है।

TAPI पाइपलाइन क्या है?

- ✓ TAPI पाइपलाइन, जिसे ट्रांस-अफगानिस्तान पाइपलाइन भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है।
- ✓ इसे गाल्किनिश - TAPI पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड द्वारा एशियाई विकास बैंक (ADB) की मदद से विकसित किया जा रहा है।
- ✓ इस पाइपलाइन का उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गाल्किनिश गैस क्षेत्र से गैस को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुँचाना है।
- ✓ इस परियोजना पर तुर्कमेनिस्तान में 13 दिसंबर 2015 को काम शुरू हुआ था, और अफगानिस्तान में फरवरी 2018 में कार्य शुरू हुआ। हालांकि, 2022 तक परियोजना के निर्माण में देरी हो चुकी है।

TAPI पाइपलाइन का मार्ग:

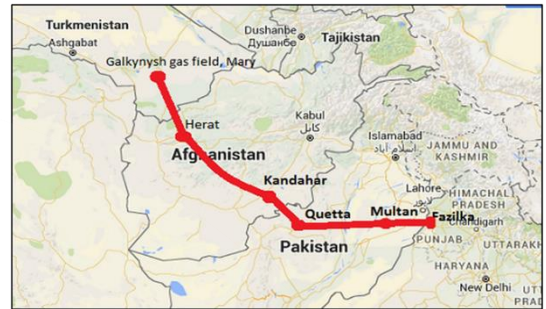
- ✈ यह पाइपलाइन लगभग 1,814 किलोमीटर लंबी होगी और तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक जाएगी।
- ✈ इसका मार्ग तुर्कमेनिस्तान के मैरी क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान में कंधार और हेरात से होकर गुजरेगा।
- ✈ फिर यह पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान शहरों को पार करेगी और भारत के पंजाब राज्य में फाजिल्का तक पहुँचेगी।

TAPI पाइपलाइन के वित्तीय स्रोत:

TAPI परियोजना का वित्तीय प्रबंध एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा किया जा रहा है। ADB इस परियोजना को आर्थिक सलाह देने वाली संस्था भी है।

TAPI पाइपलाइन के लाभ:

- ✨ यह पाइपलाइन चार देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देगी और साथ ही शांति और सुरक्षा को मजबूत करेगी।
- ✨ अनुमानित रूप से 1.5 अरब लोग इस परियोजना से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का लाभ उठाएँगे।
- ✨ तुर्कमेनिस्तान को गैस की बिक्री से राजस्व प्राप्त होगा, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पारगमन शुल्क से भी लाभ होगा।
- ✨ हालांकि, अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा समस्याओं के कारण परियोजना में देरी हो गई है।



TAPI पाइपलाइन का भारत के लिए महत्व:

- ✈ भारत के लिए TAPI पाइपलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत को मध्य एशिया के ऊर्जा स्रोतों से जुड़ने का मौका मिलेगा।
- ✈ भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस परियोजना से लाभान्वित हो सकता है।
- ✈ BP एनर्जी आउटलुक 2035 के अनुसार, भारत की ऊर्जा मांग में भारी वृद्धि होगी, लेकिन घरेलू उत्पादन से इसे पूरा नहीं किया जा सकेगा।
- ✈ इसी कारण भारत को TAPI परियोजना से बड़ी उम्मीदें हैं, जो उसे ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया से जोड़ेगी।
- ✈ इस पाइपलाइन से चार देशों के बीच न केवल ऊर्जा का आदान-प्रदान होगा, बल्कि व्यापार और विश्वास में भी वृद्धि होगी, जिससे पूरे क्षेत्र को आर्थिक और सामरिक रूप से फायदा मिलेगा।

परियोजना की चुनौतियाँ:

- ✨ सुरक्षा: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में सुरक्षा चुनौतियाँ परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- ✨ वित्तपोषण और निर्माण: परियोजना की वित्तपोषण आवश्यकताओं को अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है, और इसके चालू होने में देरी की संभावना बनी हुई है।



WHO ने एंटीबायोटिक प्रदूषण से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार दवा निर्माण प्रक्रिया से होने वाले एंटीबायोटिक प्रदूषण से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह एंटीबायोटिक उत्सर्जन, जो बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) संकट का एक प्रमुख कारण है, को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एंटीबायोटिक प्रदूषण और AMR संकट:

दवा निर्माण के दौरान उत्सर्जित एंटीबायोटिक अवशेष युक्त अपशिष्ट जल जलाशयों और भूमि को प्रदूषित करता है। इस प्रदूषण के कारण एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) बढ़ता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य संकट का मुख्य कारण बन चुका है। वर्तमान में, एंटीबायोटिक प्रदूषण पर कड़े नियम नहीं हैं, और अधिकांश गुणवत्ता मानक पर्यावरणीय उत्सर्जन को संबोधित नहीं करते हैं।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) क्या है?

AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। WHO के अनुसार, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसका तेजी से फैलाव मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से दवाओं के अति प्रयोग और गलत उपयोग के कारण हो रहा है। "सुपरबग्स" का निर्माण भी इसी का परिणाम है, जो रोगियों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

AMR से संबंधित मुख्य चिंताएँ:

- स्वास्थ्य पर प्रभाव:** AMR को WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में शामिल किया है। 2019 में, लगभग 1.27 मिलियन लोग एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण मारे गए।
- पर्यावरणीय नुकसान:** AMR से न केवल मानव स्वास्थ्य पर, बल्कि जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्रदूषण और जूनोटिक रोगों के प्रसार को बढ़ावा देता है।
- खाद्य और कृषि सुरक्षा:** AMR कृषि और पशुपालन के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
- आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:** AMR के कारण उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि और गरीबी में इजाफा हो रहा है।

AMR से निपटने के लिए प्रमुख पहल:

- एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण (One Health Approach): इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को संतुलित और बेहतर बनाना है। यह AMR से निपटने के लिए एक समग्र और टिकाऊ तरीका है।
- गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP), 2020: WHO द्वारा जारी ये दिशानिर्देश विनिर्माण प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभावों, जैसे अपशिष्ट प्रबंधन, पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR), 2017: इस योजना के तहत 40 अनुचित दवा संयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया और मुर्गी पालन में कोलिसेन के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है।
- एंटीमाइक्रोबियल वैक्सीन का विकास: भारत बायोटेक और अमेरिकी फर्म के सहयोग से एंटीमाइक्रोबियल वैक्सीन AV0328 का विकास किया जा रहा है।



विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर काम करता है।
- ✓ इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और
- ✓ इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- ✓ वर्तमान में WHO के 194 सदस्य देश हैं।
- ✓ WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना है।

WHO के प्रमुख कार्य:

- बीमारियों की रोकथाम: WHO विभिन्न बीमारियों जैसे मलेरिया, पोलियो, HIV/AIDS, टीबी, और अन्य संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में मदद करता है।
- वैश्विक स्वास्थ्य नीति निर्धारण
- स्वास्थ्य संकटों का प्रबंधन
- स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण
- तकनीकी सहायता
- यह संगठन स्वास्थ्य से जुड़े शोध कार्यों को भी प्रोत्साहित करता है।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)

Only at
99/-Year
Enroll Now!

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह एकल खिड़की पहल तेज़, सुलभ और परिवर्तनकारी है तथा यह निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा। 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर का माल निर्यात और एक ट्रिलियन डॉलर का सेवा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म के बारे में -

- ✓ ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म (<https://trade.gov.in>) एक अत्याधुनिक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से मध्यम, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तस्वीर बदलना है।
- ✓ यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई मंत्रालय, एक्सिम बैंक, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), और विदेश मंत्रालय (एमईए) जैसे प्रमुख भागीदारों के सहयोग से विकसित किया गया है, जो निर्यातकों को व्यापार के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन प्रदान करता है।

व्यापार से जुड़ी जानकारी तक रियल टाइम पहुंच:

- ✦ यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक लगभग रियल टाइम में पहुंच प्रदान करता है।
- ✦ यह उन्हें भारतीय मिशनों, वाणिज्य विभाग, निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार विशेषज्ञों से जोड़ता है। चाहे कोई नया निर्यातक हो या अनुभवी, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म निर्यात यात्रा के हर चरण में उपयोगी है।

प्लेटफॉर्म की व्यापक नेटवर्किंग:

यह ई-प्लेटफॉर्म 6 लाख से अधिक आईईसी धारकों, 180 से अधिक भारतीय मिशन अधिकारियों, 600 से अधिक निर्यात संवर्धन परिषद अधिकारियों और डीजीएफटी, डीओसी, बैंकों के अधिकारियों को एक साथ जोड़ता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम माध्यम है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक कदम:

- ✦ ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म का उद्देश्य निर्यातकों को अधिक कुशलता से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना, व्यापार समझौतों का लाभ उठाना और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है।
- ✦ इससे उच्च निर्यात मात्रा, बाजारों का विस्तार और भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी, जिससे देश की समग्र आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप पहल:

- ✦ यह पहल भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की सोच के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।
- ✦ यह व्यापार से जुड़े खर्च, लीड समय और जटिलताओं को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है।
- ✦ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।



प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुविधाएं:

- उत्पाद और कंटी गाइड:** विस्तृत बाजार अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- व्यापार समझौते और टैरिफ एक्सप्लोर:** मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लाभों को उजागर करता है।
- वैश्विक ई-कॉमर्स गाइड:** ऑनलाइन बाजारों में सफलता के लिए मार्गदर्शन।
- एक्सिम पाठशाला:** निर्यातकों को वैश्विक व्यापार में महारत हासिल करने के लिए शिक्षा प्रदान करता है।
- सोर्स फ्रॉम इंडिया:** भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करता है।
- आस्क एन एक्सपर्ट:** व्यापार पेशेवरों से रियल टाइम सलाह प्राप्त करने की सुविधा।

2024
GA FOUNDATION
RECORDED BATCH

Subject: HISTORY, POLITY, GEOGRAPHY, ECONOMICS

Price: **1499/-**

Validity: 1 Year

By Ankit Avasthi Sir

SSC TEST SERIES
CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)

Only at **99/-Year**
Enroll Now!



आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत PM-JAY)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है।

योजना के प्रमुख बिंदु:

1. कवरेज का विस्तार:

- ✓ **सर्वेक्षण की मान्यता:** इस मंजूरी के साथ, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, आयुष्मान भारत PM-JAY का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- ✓ **नया कार्ड:** पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले से कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा, जिसे वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करेंगे।

2. मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं का विकल्प:

- ✦ **अन्य योजनाओं के लाभार्थी:** 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही सीजीएस, ईसीएस, या आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत PM-JAY का विकल्प चुन सकते हैं।
- ✦ **प्राइवेट बीमा पॉलिसियां:** वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे भी आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे।

3. योजना का विवरण:

- ✦ **दुनिया की सबसे बड़ी योजना:** आयुष्मान भारत PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
- ✦ **लाभार्थियों का विस्तार:** इस योजना में 49 प्रतिशत महिला लाभार्थियों सहित 7.37 करोड़ लाभार्थियों ने अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया है। जनता को इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ है।



Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

योजना विस्तार की घोषणा:

- ✦ **सार्वजनिक घोषणा:** 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवर के विस्तार की घोषणा पहले अप्रैल 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
- ✦ **लाभार्थी आधार का विस्तार:** प्रारंभ में, इस योजना के तहत भारत की निचली 40% आबादी वाले 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल किया गया था। बाद में, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर, लाभार्थी आधार को 12 करोड़ परिवारों तक बढ़ा दिया गया।
- ✦ **आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का लाभ:** देश भर में काम करने वाली 37 लाख आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना का और विस्तार किया गया है।

आयुष्मान भारत PM-JAY योजना अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करेगी, जो व्यापक और समावेशी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सारथी ऐप (Saarthi App)

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने व्यवसायों को अनुकूलित खरीदार-साइड ऐप्स बनाने में सहायता के लिए **सारथी** नामक एक **नई रेफरेंस एप्लिकेशन** लॉन्च की है। यह ऐप **Bhashini** के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है, जो एक **AI-चालित भाषा अनुवाद** उपकरण है। सारथी नेटवर्क भागीदारों को **ONDC** के साथ सहज एकीकरण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है और बहुभाषी क्षमताओं को उन्नत करता है।



सारथी ऐप की प्रमुख विशेषताएँ:

- ✓ **बहुभाषी समर्थन:** सारथी ऐप शुरू में **हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला और तमिल भाषाओं** का समर्थन करता है, और भविष्य में **Bhashini** द्वारा प्रदान की गई **22 भाषाओं** तक विस्तार करने की योजना है। यह व्यवसायों को एक **व्यक्तिगत और स्थानीयकृत खरीदारी अनुभव** प्रदान करता है, जो भाषा की बाधाओं को तोड़ता है और पूरे भारत में उपयोगकर्ताओं की पहुंच बढ़ाता है।
- ✓ **वास्तविक समय अनुवाद:** सारथी की बहुभाषी सुविधाओं में **वास्तविक समय अनुवाद, लिप्यंतरण** (किसी भाषा के अक्षरों या वर्णों को किसी दूसरी भाषा के अक्षरों या वर्णों में बदलना) और **आवाज पहचान** शामिल हैं। ये तकनीकें व्यवसायों को बाजार पहुंच का विस्तार करने और ग्राहक अधिग्रहण बढ़ाने में मदद करती हैं।
- ✓ **उन्नत ग्राहक अनुभव:** एप्लिकेशन का उद्देश्य **व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान** करना है, जिससे **ग्राहक जुड़ाव और वफादारी** को बढ़ावा मिलता है। स्थानीयकृत अनुभव उच्च रूपांतरण दरों और कम समर्थन लागतों को प्रोत्साहित करता है, जिससे संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और **राजस्व को बढ़ावा** मिलता है।
- ✓ **स्केलेबिलिटी और एकीकरण में आसानी:** सारथी को **स्केलेबिलिटी और एकीकरण** की आसानी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। निरंतर अपडेट सुनिश्चित करते हैं कि व्यवसाय नवीनतम सुविधाओं और सुरक्षा सुधारों से लाभान्वित हो सकें, और समाधान की विश्वसनीयता व्यापक परीक्षण और विशेषज्ञता द्वारा समर्थित है।

सारथी ऐप की विशेषताएँ कम सेवा वाले क्षेत्रों और समुदायों तक पहुंचने में विशेष रूप से लाभकारी हैं, जहां भाषा की बाधाएँ ई-कॉमर्स अपनाने में एक प्रमुख चुनौती रही हैं।

Bhashini के बारे में:

Bhashini एक भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन के तहत एक परियोजना है जिसका उद्देश्य **भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में तकनीकी अनुवाद सेवाएं** प्रदान करना है। इसका मतलब है कि Bhashini के माध्यम से, हम किसी भी भाषा में लिखे गए **टेक्स्ट को दूसरी भाषा में आसानी से अनुवाद** कर सकते हैं।

Bhashini का महत्व:

- **समावेशी विकास:** यह उन लोगों तक **तकनीक और जानकारी** पहुंचाने में मदद करता है जो केवल अपनी मातृभाषा बोलते हैं।
- **डिजिटल भारत:** यह भारत को एक **डिजिटल समाज** बनाने की दिशा में एक कदम है जहां सभी को समान अवसर मिलें।
- **आर्थिक विकास:** यह **छोटे व्यवसायों को अपनी पहुंच बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश** करने में मदद कर सकता है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य **डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में नवाचार और प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा देना है। ONDC को एक **खुला, इंटरऑपरेबल और बहु-परिधि मंच** बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ई-कॉमर्स के पारंपरिक मॉडल को चुनौती देता है और **छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं** को समान अवसर प्रदान करता है।

ONDC के प्रमुख उद्देश्य:

- **विपणन का लोकतंत्रीकरण:** ONDC का मुख्य लक्ष्य **छोटे व्यापारियों और स्थानीय विक्रेताओं को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों** के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका देना है। यह अधिक पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- **इंटरऑपरेबल नेटवर्क:** यह नेटवर्क विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों, ऐप्स और सेवाओं के बीच **seamless इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम** बनाता है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को एकीकृत डिजिटल अनुभव मिलता है।
- **व्यापक पहुंच:** ONDC का उद्देश्य **ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में व्यापारियों को भी डिजिटल व्यापार के लाभ प्रदान** करना है, ताकि वे भी **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों** में अपने उत्पाद और सेवाएँ बेच सकें।
- **टेक्नोलॉजी और डेटा पर नियंत्रण:** ONDC **विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को उनके डेटा पर अधिक नियंत्रण** प्रदान करता है, जिससे वे अपनी **डिजिटल उपस्थिति** को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।

सिद्ध औषधियों से किशोरियों में एनीमिया का सफल उपचार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है और इसके लिए दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

योजना के प्रमुख घटक:

1. ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू और ई-बसों के लिए प्रोत्साहन:

- ✓ **वित्तीय सहायता:** इस योजना के तहत 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों को सहायता प्राप्त होगी।
- ✓ **ई-वाउचर प्रणाली:** ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश किया जाएगा, जिसे आधार प्रमाणित किया जाएगा और योजना के पोर्टल पर जारी किया जाएगा। ई-वाउचर का उपयोग करके डीलर को प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त होगा।

2. ई-एम्बुलेंस को प्रोत्साहन:

- ✓ **वित्तीय आवंटन:** ई-एम्बुलेंस को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पहल मरीजों के आरामदायक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए है, और इसके प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों का विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा।

3. ई-बसों के लिए समर्थन:

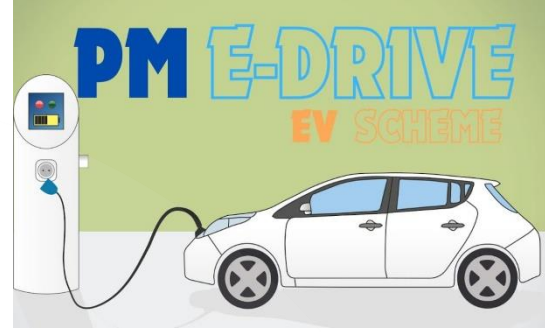
- ✓ **धनराशि:** राज्य परिवहन निगमों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ प्रमुख शहरों में मांग एकत्रीकरण किया जाएगा। पुराने एसटीयू बसों को स्कैप करने के बाद नई बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. ई-ट्रकों के प्रोत्साहन:

- ✓ **वित्तीय आवंटन:** ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये ट्रक वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगे, और एमओआरटीएच द्वारा अनुमोदित वाहन स्कैपिंग केंद्रों से स्कैपिंग प्रमाण पत्र वाले वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

5. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास:

- ✓ **ईवी चार्जिंग स्टेशन:** योजना के तहत ई-4 डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर, और ई-2 डब्ल्यू/3 डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।



योजना का उद्देश्य और लाभ:

- ⇨ **पर्यावरणीय प्रभाव कम करना:** पीएम ई-ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद को प्रोत्साहित करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। यह योजना वायु की गुणवत्ता में सुधार और टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
- ⇨ **आत्मनिर्भर भारत:** योजना एक कुशल और प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे घरेलू विनिर्माण और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा।
- ⇨ **रोजगार सृजन:** विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना से महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा होंगे, जो देश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित होगा।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)

Only at
99/-/Year
Enroll Now!

मिशन मौसम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मिशन मौसम' को अगले दो वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में मौसम और जलवायु-संबंधी विज्ञान, अनुसंधान, और सेवाओं को बेहतर बनाना है।

मिशन मौसम की प्रमुख विशेषताएं:

- ✓ मिशन मौसम, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा, एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल है।
- ✓ इसका उद्देश्य मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए नागरिकों और अन्य हितधारकों को बेहतर रूप से तैयार करना है।
- ✓ यह कार्यक्रम न केवल मौसम पूर्वानुमान में सुधार करेगा, बल्कि दीर्घकालिक रूप से समुदायों, क्षेत्रों और इकोसिस्टम की क्षमता और अनुकूलन में भी वृद्धि करेगा।

मिशन का वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण:

- ✦ मिशन के तहत, वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान और विकास, विशेष रूप से मौसम निगरानी, मॉडलिंग, और पूर्वानुमान के क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया जाएगा।
- ✦ उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके मौसम की अधिक सटीक भविष्यवाणी का नया मानदंड स्थापित किया जाएगा।

मौसम की जानकारी में सुधार:

- ✓ मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य बेहतर अवलोकन और समझ के साथ अस्थायी और स्थानिक पैमानों पर अत्यधिक सटीक एवं समय पर मौसम और जलवायु जानकारी प्रदान करना है।
- ✓ इसमें मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता चेतावनी, मौसम की चरम घटनाएं (जैसे चक्रवात, ओले, वर्षा आदि) और अन्य मौसम संबंधी उपाय शामिल हैं। मिशन में क्षमता निर्माण और जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जाएगा।

मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा:

- ✦ भारत मौसम विज्ञान विभाग,
- ✦ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और
- ✦ राष्ट्रीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग की "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV (PMG-SY-IV)" को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक कार्यान्वित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क मार्ग प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण और पुलों का निर्माण/उन्नयन शामिल है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्यांश 21,037.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य जनगणना 2011 के अनुसार असंबद्ध बस्तियों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना है।

योजना का विस्तार और लक्ष्य:

- ✦ लक्षित बस्तियाँ: 25,000 असंबद्ध बस्तियाँ, जिनमें मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाली, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250+, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजाति अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली बस्तियाँ शामिल हैं।
- ✦ सड़क निर्माण: इस योजना के तहत इन बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की आल वेदर रोड प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

योजना के लाभ:

- ✦ सामाजिक-आर्थिक विकास: आल वेदर रोड से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा और ये मार्ग स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार लाएंगे। जहां संभव हो, इन सड़कों को पास के सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और विकास केंद्रों से जोड़ा जाएगा।
- ✦ निर्माण की गुणवत्ता: पीएमजीएसवाई - IV में अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक, पैनल सीमेंट कंक्रीट, सेल फिल्ड कंक्रीट, फुल डेथ रिक्लेमेशन, निर्माण अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट जैसे फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग का उपयोग किया जाएगा।
- ✦ डिजिटल समर्थन: पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से सड़क संरेखण और योजना टूल्स की सहायता से डीपीआर तैयार किया जाएगा।

पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद और संचालन के लिए "पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)" योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 3,435.33 करोड़ रुपये का परिचय निर्धारित किया गया है और यह 2024-25 से 2028-29 तक लागू होगी।



योजना के प्रमुख बिंदु:

1. योजना की विस्तृत जानकारी:

- ✓ **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। ई-बसों की तैनाती की तारीख से 12 साल तक के लिए उनकी संचालन लागत को भी सहारा मिलेगा।
- ✓ **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में अधिकांश सार्वजनिक परिवहन बसें डीजल या सीएनजी पर चलती हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ई-बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और उनकी परिचालन लागत भी कम होती है।

2. वित्तीय सहायता और भुगतान सुरक्षा:

- ✦ **जीसीसी मॉडल:** ई-बसों की ऊंची पूंजी लागत के समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) जीसीसी (ग्रेस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल का उपयोग करेंगे। इस मॉडल के तहत, पीटीए को बस की अग्रिम लागत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ओईएम/ऑपरेटर मासिक भुगतान के साथ ई-बसों की खरीद और संचालन करेंगे।
- ✦ **भुगतान सुरक्षा:** योजना एक समर्पित कोष के माध्यम से ओईएम/ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। पीटीए द्वारा भुगतान में चूक के मामलों में, सीईएसएल योजना निधि से आवश्यक भुगतान करेगी, जिसे बाद में पीटीए/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुकता किया जाएगा।

3. योजना के लाभ:

- ✦ **पर्यावरणीय लाभ:** इस योजना से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन की खपत घटेगी।
- ✦ **प्रोत्साहन:** योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है और ई-बसों की व्यापक तैनाती को आसान बनाना है।
- ✦ **लाभार्थी:** इस योजना का लाभ उन सभी सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों को होगा जो इसे अपनाएंगे, विशेष रूप से राज्य और संघ शासित प्रदेशों में।

नमक पैन भूमि (Salt Pan Lands)

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई में 256 एकड़ नमक पैन भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना निजी लिमिटेड (DRPPL) को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना अडानी रियल्टी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसका लक्ष्य झुग्गीवासियों के लिए किराये के आवास निर्माण करना है।



नमक पैन भूमि क्या होती है?

- ✓ **परिभाषा:** नमक पैन भूमि उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां समुद्री जल कुछ समय के लिए बहता है और नमक व अन्य खनिज छोड़ता है।
- ✓ **पारिस्थितिक भूमिका:** मुंबई के मैंग्रोव्स के साथ मिलकर, नमक पैन भूमि शहर को बाढ़ से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ✓ **2017 के वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों के अनुसार, नमक पैन भूमि को वेटलैंड की परिभाषा से हटा दिया गया है।**
- ✓ **विनियमन:** 2011 के तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना के तहत, ये भूमि CRZ-1B श्रेणी में आती है, जहां केवल नमक निष्कर्षण और प्राकृतिक गैस अन्वेषण की अनुमति है। अन्य आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ निषिद्ध हैं।

मुंबई में नमक पैन भूमि की स्थिति:

- ✦ **भूमि का क्षेत्रफल:** मुंबई में कुल 5,378 एकड़ भूमि को नमक पैन के रूप में नामित किया गया, जो धारावी झुग्गी के आकार का लगभग नौ गुना है।
- ✦ **वर्तमान स्थिति:** इस भूमि का लगभग 31% आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित है। 2014 के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 480 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।
- ✦ **राष्ट्रीय स्तर पर:** भारत में कुल 60,000 एकड़ भूमि को नमक पैन के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र (12,662 एकड़), आंध्र प्रदेश (20,716 एकड़), और तमिलनाडु (17,095 एकड़) शामिल हैं।

मुंबई की नमक पैन भूमि पर संभावित खतरा:

- ✦ **भूमि की मांग:** मुंबई में भूमि की अत्यधिक मांग के बावजूद, नमक पैन भूमि अब तक संरक्षित रही, लेकिन भविष्य में इस पर खतरा बना हुआ है।
- ✦ **विकास योजनाएँ:** राज्य सरकारों ने झुग्गीवासियों के लिए कम लागत वाले आवास निर्माण जैसे विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए इन भूमि का उपयोग करने की योजनाएँ बनाई हैं। 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलुंड में नमक पैन भूमि पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन उनकी योजनाएँ 2019 में रोक दी गई थीं। वर्तमान में धारावी में नमक पैन भूमि पर किफायती आवास बनाने की योजना है।

मायरिक्टिका दलदली जंगल (Myristica swamp forest)

हाल ही में गोवा-महाराष्ट्र सीमा के पास शोधकर्ताओं ने कुंब्राल, महाराष्ट्र में एक मायरिक्टिका दलदली जंगल (Myristica swamp forest) की खोज की है। यह खोज स्थानीय समुदायों द्वारा दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने के महत्व को उजागर करती है। इस क्षेत्र को सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया गया है।



मायरिक्टिका मैग्निफिका क्या है?

- ✓ **परिचय:** मायरिक्टिका मैग्निफिका एक लुप्तप्राय पौधा प्रजाति है जो मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में पाई जाती है।
- ✓ **विशेषताएँ:** यह पेड़ 50 मीटर तक ऊँचा हो सकता है और जायफल परिवार का हिस्सा है। इसके बीज जायफल से मिलते-जुलते हैं, लेकिन कम मूल्यवान होते हैं।
- ✓ **उपयोग:** इसकी लकड़ी का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है और इसके तेल में अरोमाथेरेपी के गुण होते हैं।
- ✓ **महत्व:** यह पौधा पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खतरों में पड़े हॉर्नबिल पक्षियों सहित वन्य जीवन के लिए भोजन प्रदान करता है।

खोज का महत्व:

- ✦ **पवित्र स्थल:** कुंब्राल में स्थित मायरिक्टिका दलदली जंगल, महाराष्ट्र में हेवले-बंबाई के बाद दूसरा स्थान है, जिसमें इस प्रकार का जंगल है। स्थानीय समुदाय ने इसे भगवान शिव से जुड़ा हुआ मानते हुए लंबे समय से संरक्षित किया है।
- ✦ **आकर्षण:** यह ग्रोव 8,200 वर्ग मीटर में फैला है और 39 विभिन्न पौध प्रजातियों का घर है, जिसमें 70 मायरिक्टिका मैग्निफिका पेड़ शामिल हैं।
- ✦ **पारिस्थितिक सेवाएँ:** इस दलदली जंगल की विशेषताएँ शामिल हैं भूजल पुनर्भरण, कार्बन पृथक्करण, और बाढ़ शमन।
- ✦ **महत्व:** अध्ययन से पता चलता है कि यह मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र कई प्रजातियों के लिए आवश्यक है, जिसमें कमजोर एशियाई शॉर्ट-क्लाड ओटर भी शामिल है।

पारिस्थितिक महत्व:

- ✦ **कार्बन संग्रहण:** ये दलदल बड़ी मात्रा में कार्बन संग्रह करते हैं, जिससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है।
- ✦ **जैव विविधता:** वनस्पतियों और जीवों के मिश्रण के साथ, ये दलदल पश्चिमी घाट में जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मिकानिया माइक्रान्था

हाल ही में भद्रा टाइगर रिजर्व में मिकाना माइक्रान्था नामक खरपतवार बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे वहां की जैव विविधता को खतरा हो रहा है।

मिकाना माइक्रान्था के बारे में:

- ✓ **परिचय:** मिकाना माइक्रान्था एक बारहमासी रेंगने वाला चढ़ाई वाला पौधा है, जिसे अपने तीव्र और जल्दी विकास के लिए जाना जाता है।
- ✓ **उत्पत्ति:** यह पौधा मध्य और दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है, और अब यह दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और प्रशांत द्वीपों के कई हिस्सों में एक प्रमुख आक्रामक प्रजाति बन चुका है।
- ✓ **भारत में आगमन:** इसे 1940 के दशक में भारत में चाय बागानों में जमीनी कवर के रूप में पेश किया गया था, और अब यह बागान फसलों और वन क्षेत्रों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।
- ✓ **विकास की स्थिति:** यह पौधा उच्च उर्वरता, कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी की नमी और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में तेजी से फैलता है।
- ✓ **प्रभाव:** यह अन्य पौधों की वृद्धि को रोकता है, उन्हें दबाकर या प्रकाश को अवरुद्ध करके नुकसान पहुंचाता है।
- ✓ **प्रजनन:** मिकाना माइक्रान्था हजारों हल्के बीज पैदा करता है जो हवा से फैलते हैं, और इसके रूट्स वानस्पतिक प्रजनन के माध्यम से तेजी से फैलते हैं।



भद्रा टाइगर रिजर्व के बारे में:

- ✦ भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र के बीच स्थित है।
- ✦ यह रिजर्व पहाड़ी श्रेणियों के बीच स्थित है और हाथियों की अच्छी आबादी के लिए जाना जाता है। यह एक हाथी रिजर्व भी है।
- ✦ इसे 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।

अभयारण्य की विशेषताएँ:

- ✦ **रिवर टर्न लॉज:** भद्रा जलाशय के किनारे, लक्कवली के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। यह अभयारण्य की उत्तरी सीमा से बहुत करीब है।
- ✦ **मुथोड़ी:** यह अभयारण्य का सबसे सुंदर वन क्षेत्र है।
- ✦ **जगरा जायंट:** यह राज्य का सबसे बड़ा चीकू का पेड़ है, जिसकी परिधि 5.1 मीटर और ऊंचाई 32 मीटर है, और यह लगभग 400 वर्ष पुराना माना जाता है।
- ✦ **क्षेत्रफल:** भद्रा टाइगर रिजर्व लगभग 500 वर्ग किमी में फैला है, जो शिवमोगा और चिकमगलूर जिलों में स्थित है।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!





APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Pathshala
एथिका ज्ञानेन अध्यायंति विद्यां

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

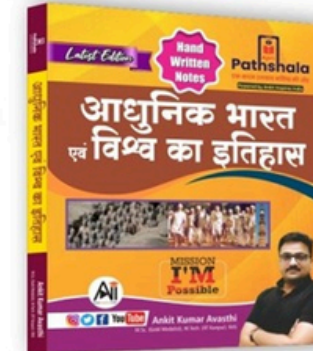
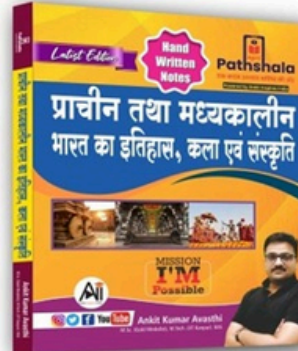
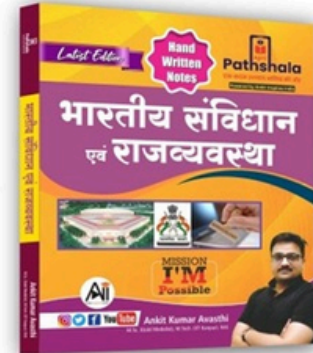
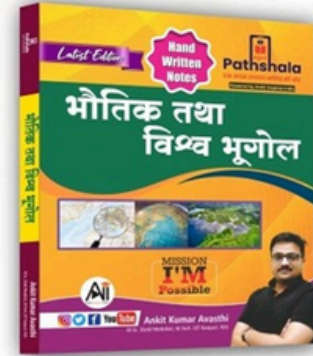
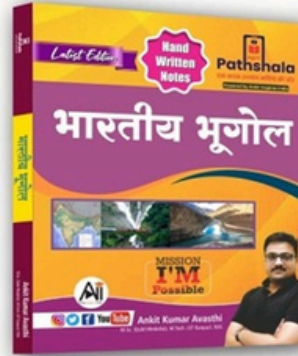
Hand Written
Notes


Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ankit Inspires India

₹ Only
1999

4 पुस्तकों
का
सम्पूर्ण सेट



अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**